

[Secretary]

assented to by the President since a report was last made to the House on the 3rd April, 1967:

- (1) The Armed Forces (Special Powers) Continuance Bill, 1967.
- (2) The Representation of the People (Amendment) Bill, 1967.
- (3) The Land Acquisition (Amendment and Validation) Bill, 1967.
- (4) The Essential Commodities (Amendment) Bill, 1967.

12-34 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

FIRST REPORT

Shri Khadiilkar (Khed): I beg to present the First Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.42 hrs.

STATEMENT ON UK'S RENEWED APPLICATION FOR ENTRY INTO E.C.M.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): Sir, hon. Members would have known from recent announcements that the British Government have made an application on the 11th May, 1967 for admission of the United Kingdom to the European Economic Community....

Shri Nath Pal (Rajapur): We have studied the statement and we are ready with questions.

Shri Ranga (Srikakulam): We did not know that this was being placed somewhere and we had to go there and get it.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Barh): I have not got it.

Mr. Speaker: I am told it has been circulated. Then, he may lay it on the Table of the House.

Shri Dinesh Singh: I have no objection. I lay on the Table [Placed in Library. See No. LT-340/87].

Shri Nath Pal: Are you ready to answer?

Shri Dinesh Singh: Yes.

श्री मधु लिंगम (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रवेश पाने के लिए जो प्रयत्न दो है उनका हिन्दुस्तान के व्यापार पर क्या असर पड़ने वाला है उस को लेकर यह बयान दिया है। 21 साल की उम्र होने पर कोई भी व्यक्ति वाणिज्य हो जाना है, जब स्वतन्त्रता के बाद करीब करीब 21 साल हो रहे हैं, वेही समय में नहीं था रहा है कि हमारी सरकार जब वाणिज्य होने वाली है ? इसमें जो विचारधारा है, वही राष्ट्रमंडल के मुद्दे को गंभीर बनाने की विचारधारा है, वही प्रवृत्तियों के साथ जो पुराने व्यापारी नियम थे, उनको बनाये रखने की विचारधारा है। यूरोप में और दुनिया में जो बड़े बड़े परिवर्तन आये हैं, उनके अनुकूल अपनी नीति का बनाने की इसमें इच्छा नहीं दिखाई दे रही है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि अपने निर्यात व्यापार के मामले में जो हम प्रवृत्तियों पर ज्यादा मुनहमिर रहते हैं, उसको कम करने के लिये तथा दूसरे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाते जा रही है ? धारा जब कि फॉर्म के अध्यक्ष जेनरल डिगाम साहब ने स्टिमिंग के बारे में कुछ आरोप उठाये हैं, फिर भी हम लोग स्टिमिंग एरिया के सदस्य हैं। अतः मंत्री महोदय इस बात का सुनासा करें कि कौनम मार्केट के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये किस तरह की कार्यवाही की जा रही है ? जो बातचीत होने वाली है, उसका नेतृत्व कौन करने वाले हैं और प्रवृत्तियों के ऊपर हर मामले में